मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना

*43. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगें कि:

(क) क्या दिल्ली में 1995 के अन्त तक "मांग पर सभी को टेलीफोन उपलब्ध" कराने के संबंध में सरकार के आश्वासन को पूरा किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) दिल्ली में 31.10.95 की स्थिति के अनुसार 1,17,743 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। वर्ष 1995-96 के लिए 2,72,700 सीधी एकसचेंज लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। अत: यह आशा की जाती हैं कि इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिसंख्य आवेदकों को मार्च 96 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में दिल्ली सहित सम्पूर्ण देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होने कहा था कि 1995 के अंत तक दिल्ली में मांग पर सभी को टेलीफोन उपलब्ध कराए जायेंगे। किन्तु मुझे खेद हैं कि जैसा कि उनका नाम हैं, सुखराम वैसा उनका काम नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि 31.10.1995 तक 1,17,743 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। .....**(व्यवधान)**..... मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1994-95 का लक्ष्य क्या था और उसमें कितने की पूर्ति की गई हैं। (ब) मेरा प्रश्न हैं यह जो प्रतीक्षा-सूची 31.10.95 तक की हैं, यह तो अंतिम तिथि है लेकिन कब से हैं, यह भी बताने की कृपा करेंगे? साथ ही प्रतीक्षा सूची जो बतायी गई हैं वह किस-किस श्रेणी की हैं, इसका विवरण दें और मांग के अनुसार पूर्ति का प्रतिशत क्या हैं?

श्री सुखराम : सभापति महोदय, मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा था कि यह एश्योरेंस मैंने पार्लियामेंट में दिया हुआ हैं कि 1995 में हम प्रतीक्षा-सूची को खत्म करेंगे। मगर फिर भी हम यह मानकर चलते हैं कि शायद जो यहां पर मेयर ने बात उठाई हैं, उसको भी अगर मानकर चलें तब भी हमारा जो लक्ष्य हैं इस साल का, वह 2,72,700 हैं और उसमे जो 52 हजार हम दे चुके हैं और । लाख 17 हजार के लिए हमारी कोशिश हैं। कुल एक्विपमेंट न मिलने की वजह से उसमें देरी तो हो गई, मगर मार्च के अंत तक अभी जो वेटिंग लिस्ट हैं 1 1 लाख 17 हजार की, इसको देने की कोशिश करेंगे। नेशनल टेलीकाम पालिसी में हमने सारे देश से वायदा किया हैं कि 1997 में हम सारी प्रतीक्षा सूची को खत्म कर देंगे और उसमें दिल्ली भी शामिल हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने अपना जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि यह प्रतीक्षा सूची जो दी गई हैं वह कब से पेडिंग हैं और किस श्रेणी की हैं? उनका लक्ष्य क्या था और कितनों की पूर्ति की गई 95 तक। इसका पहले जवाब दें, फिर दूसरा सप्लीमेंटी पूछूंगा।

श्री सुखराम : सभापति महोदय, जो वेटिंग लिस्ट हैं वह 31.10.95 तक की हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी : कब से शुरू होती हैं?

श्री सुखराम : 31.10.95 तक की वेटिंग लिस्ट हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसकी शुरूआत कब से हैं?

श्री सुखराम : यह जो साल से ज्यादा की नहीं हैं। यह जो प्रतीक्षा सूची हैं यह दो साल से ज्यादा की नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri V.P. Duraisamy.

SHRI DIGVIJAY SINGH: He has to put his second supplementary, Sir.

MR. CHAIRMAN: I thought that he had put his second supplementary also.

श्री गोविन्दराम मिरी : मेरा सेंकड सप्लीमेंटरी।

माननीय मंत्री जी ने अभी जो कहा दो साल से पहले की नहीं हैं, में उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आतांरिकत प्रश्न संख्या 3183 का जो जवाब 24 अगस्त, 1995 को दिया गया था, उसमें उन्होने कहा था कि :

"Some of the persons who have booked their telephone connections during 1989 are still on the waiting list in the following States:

इसमें दिल्ली भी इन्कूड हैं, नं. 15 पर। अभी आपने कहा कि दो साल से ऊपर नहीं हैं। तो क्या 89 वालों की पूर्ति की गयी हैं? दूसरा मेरा प्रश्न हैं कि इसमें आपने बताया हैं कि अधिसंख्य आवेदकों को मार्च 96 तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे तो आपका क्या मतलब हैं? यह कितना प्रतिशत होगा क्योंकि आपने बड़ी-बड़ी होल्डिंग लगाई हैं आत्मप्रशंसा में। सरकार ने 100 मे से 96वायदे पूरे नहीं किए। क्या यह भी इसी

तरह से वायदा ताड़ने के लिए किया जा रहा हैं। 1996 तक लोगों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ग्राम पंचायतों को जो आपने टेलीफोन से जोड़ने का वायदा किया हैं, वह लक्ष्य भी पूरा होगा या नहीं होगा, यह बताने की कृपा करें?

श्री सुखराम : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो 1989 की बात कही हैं, शायद यह दिल्ली की हैं या सारे देश की हैं, मैं इसको मालूम कर लूंगा। मगर जो मेरी सूचना हैं वह यह हैं कि वेटिंग लिस्ट बढ़ती जाती हैं। आज जो वेटिंग लिस्ट हैं वह 6 महीने के बाद और बढ़ेगी। जैसे दिल्ली में हमारी ई.आर.यू. यूनिट में यह प्रोजेक्शन दिये हैं कि 1996 तक करीब 14 लाख से भी ज्यादा टेलीफोन की मांग होगा। दिल्ली में आज स्थिति ऐसी हैं कि हमारी जो सप्लाई हैं वह मांग से अधिक हैं। इस वास्ते जो आपने 1995 की बात की हैं, मैं नहीं कहता कि 1995 तक यह हो जाएगा क्योंकि दिल्ली में ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां टेलीफोन फीजिबिलिटी न होने की वजह से ज्यादा टेलीफोन हम नहीं दे सकें मगर हमारी कोशिश होगी कि 1996 तक आज की जो प्रतीक्षा सूची हैं वह खत्म होगी। मगर जो आइंदा और बढ़ेगी, इससे हम सप्लाई करेंगें।

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, I would like to know whether the Government assurance to provide telephone connections on demand in Tamil Nadu by the end of 1995 is going to be fulfilled. If so, when will it be fulfilled? If not, what are the reasons therefor?

SHRI SUKH RAM: Sir, 1 am not aware whether I made any commitment to liquidate the waiting list in Tamil Nadu by 1995. We had made this commitment to the whole nation and also in both the Houses of Parliament that by 1997 we will liquidate the entire waiting list in the entire country. But, as far as Tamil Nadu is concerned, 1 will find out whether I made some commitment and what actions are being taken in that regard.

श्रीमती वीणा वर्मा : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अभी आपने जो कहा हैं कि वेटिंग लिस्ट को हम 1997 तक पूरा कर देंगे, यह हमारा वायदा हैं। इस वेटिंग लिस्ट को और जल्दी पूरा किये जाने के लिए मैं यह जानना चाहती हूं कि अब ऐसे बहुत से टेलीफोन नहीं हैं बल्कि

दूसरे , तीसरें या आठवें टेलीफोन कनेक्शन हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां या आर्गेनाइजेशंस हैं वह सिर्फ तीन हजार रूपये से जनरल केटेगरी में टेलीफोन की डिमांड करती हैं और 9-10 टेलीफोन ले लेती हैं। आपने अपनी टेलीकॉम पालिसी में यह मेंशन किया था कि आप एक ऐफिडेविट स्कीम लागू करेंगें। इसलिए मेरा सुझाव यह हैं कि आप ऐफिडेविट भरवाएं जिसका पहला टेलीफोन हैं उसको तीन महीने के अंदर दे दें जिससे कि आपकी यह जो वेटिंग लिस्ट हैं यह नीडवेस्ड और रियालिस्टिक बन सकें और इसको आप जल्दी पूरा कर सकें। इसके लिए सरकार क्या सोच रही हैं? क्या आप ऐफिडेविट स्कीम लागू करने जा रहे हैं? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह हैं कि आप टेलीफोन आज कल ऑपटिक फाइबर बिछा कर दे रहे हैं जिसमें एक टेलीफोन की लागत लगभग 47 हजार रूपये का इनवेस्टमेंट आती हैं। महोदय, 40 प्रतिशत टेलीफोन ऐसे हैं जो कि सिर्फ रेंटल पर रहते हैं, बिल नहीं देना पड़ता हैं, फ्री काल्ज में टेलीफोन रहते हैं। अब कम्यूनिकेशन थ्रू स्काई की एक योजना हैं यू.एस. 80 (एस) वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल जिसमें सिर्फ ढाई मीटर का एंटेना लगा कर जगह-जगह थ्रू सेंटेलाइट पी.सी. कंप्यूटर, वीडियों एंड प्लेयर आदि बहुत सी सुविधाएं दे सकते हैं। सिर्फ छोटा सा इनफ्रास्ट्रक्चर लगाना है जो बाहर की कंपनियों या विदेशी में बहुत प्रचलित हैं औरा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उसे अपनाने जा रही हैं।

क्या इस सिस्टम पर भी सरकार विचार करने जा रही है कि देश में "वीसैट" को शुरू करेंगें जिससे टेलीफोन की मांग नीड वेस्ड हो सके और जल्दी इसको पूरा किया जा सके तथा इसको वायेबुल कास्ट इफेक्टिव बना सकें?

श्री सुख राम : सभापति जी, जहां तक वेटिंग लिस्ट का ताल्लुक हैं, हमको इस कन्टेक्स्ट में इसको देखना हैं कि 1991 की जो सेन्सस हैं उसमें 20 करोड़ ऐसे लोग हैं इस देश में जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी पंचवर्षीय योजना हैं उस योजना में 5,6,7 प्रतिशत जी.डी.पी. की ग्रोथ हैं फिर भी 20 करोड़ ही नहीं उसमें और एडीशन होती रही हैं। जब मैंने टेकओवर किया था तो उस समय 30 लाख की वेटिंग लिस्ट थी। 30 लाख की तो अब 50 लाख पर पहुंची हैं। मगर आज भी 25 लाख की वेटिंग लिस्ट हैं। इस वास्ते आज की जो वेटिंग लिस्ट हैं, किसी एक निर्धारित डेट की उसको तो हम खत्म कर देंगे। हम कह सकते हैं कि फलां तारीख तक खत्म कर देंगे। मगर वह बढ़ती जाती हैं। जब-जब भी लोगों को यह मालूम होता हैं कि टेलीफोन आन डिमांड

होने वाला है तो बहुत जल्दी लोगों की मांग उसमे बढ़ती जा रही हैं। इस वास्ते लिस्ट के लिए मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वेटिंग लिस्ट किस डेट में खत्म हो जाएंगी। जहां तक वीसैट का ताल्लुक हैं ....

श्रीमती वीणा वर्मा : जो अफीडेविट का मामला हैं।

श्री सुख राम : उसमे ओ.वाई.टी. की हमारी स्कीम हैं, ना ओ.वाई.टी. की हमारी स्कीम हैं। ओ.वाई.टी. में तकरीबन बहुत कम ऐसे लोग हैं। बम्बई जैसी सिटी में ओ.वाई.टी. में सैंकड़ो में लोग होंगे, ज्यादा नहीं होगे। दिल्ली में भी सैकड़ो में होंगे ज्यादा नहीं हैं। दो तीन महीने में हम उसको खत्म कर देंगे। ना ओ.वाई.टी. भी हम खत्म कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां करेंट हो गया है, आन डिमांड हो गया हैं। मगर जहां तक आपने वीसैंट की बात कही हैं, वीसैंट में हमने लाइसेंस दिए हैं प्राइवेट इडिवीजुअल्स को। मुझे मुहं जबानी याद नहीं हैं, 6-7 लाइसेंस दिए हुए हैं। वे उनको शुरू करेंगे। लोगों को इससे फायदा होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि जहां तक टेलीफोन देने की बात हैं, इसमें बहुत कमियां भी हैं, मैं मानता हूं इस बात को, मगर इन तीन चार वर्षो में बहुत बड़ा काम भी इस देश में हुआ हैं।

श्री राघवजी : सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि पूरे देश में 25 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं। जो अपेक्षा टेलीफोन विभाग से की गयी थी वह अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन 25 लाख लोगों में से ऐसे उपभोक्ता कितने हैं जो दो वर्ष से अधिक प्रतीक्षा सूची मे हैं और किस राज्य में यह संख्या सबसे अधिक हैं?

श्री सुख राम : सभापति जी, प्रश्न तो दिल्ली का हैं, मगर .....(**व्यवधान**).....

श्री राघवजी : आपने अपने उत्तर में ही कहा हैं .....(**व्यवधान**).....

श्री सुख राम : मैंने खुद ही कहा हैं। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं आपको। आपने अगर मेरी बात को ठीक ढंग से सुना होगा तो मैंने कहा था कि 30 लाख उस टाइम पर थे जब मैंने टेकओवर किया था। वे तो लिकिवीडेट हो गए, उससे भी ज्यादा हो गये हैं, 50 लाख मे हम पहुंचने वाले हैं और अभी जो सारे देश में हैं, वे 25 लाख है। ये तो बढ़ते हैं। मेरे पास यह आंकड़े तो नहीं हैं कि कितनी देरी में कोई वेटिंग लिस्ट में हैं और कहां-कहां हैं। आप उस पर सेपरेट नोटिस दीजिए तो उसका मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : ये नम्बर बढ़ रहे हैं इसमें आपको आपत्ति क्या हैं। आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं इंटेग्रेशन की बात करते हैं सारी वर्ल्ड इकामी से और टेलीफोन इतनी साधारण सुविधा हैं उसके बारे में चिंतित हो रहे हैं कि नम्बर बढ़ रहे हैं,संख्या बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही हैं।

श्री सुख राम : मैं चिंतित नहीं हूं .....(**व्यवधान**).....

श्री सतीश अग्रवाल : मेरी बात सुनिए एक सेकिंड। एम.पी.ज. का जो हमारा आउट आफ टर्न कोटा हैं 25 का उसका साल साल भर तक टेलीफोन नहीं लगता हैं। 94 के टेलिफोन्स, अब 94 का एंड आ गया हैं, लेकिन अभी तक टेलीफोन्स नहीं लगे है। टेलीफोन एडवायजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी एम.पीज. के साथ, उस में 30 डेज का नियम हैं, लेकिन एक-एक साल हो गया हैं इन एम.पीज. के रिकमंडेड केसेस को और बहुत से मैबर्स हैं जिन के केसेस नहीं हुए हैं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : 6 महीने हो गए हैं।

†**مولانا عبیداللہ خاں اعظمی:** ٦ مہینے ہو گئے ہیں-

श्री सतीश अग्रवाल : सर, आप इस में प्रोटेक्शन दीजिए। 30 डेज की लिमिट हैं।

Kindly direct the Minister to see to it that at least the out-of-turn allotment of telephones recommended by the Members of Parliament should be cleared within the prescribed period of thirty days. But even after the- expiry of one year, they have not been installed.

तो एक्सपायरी ऑफ वन इयर में भी टेलिफोन इंस्टाल नहीं हुए हैं और पैसे मांगते हैं आप के डिपार्टमेंट के लोग। कहते हैं पैसा दो .....(**व्यवधान**).....

MR. CHAIRMAN: Allow the Minister to answer.

श्री राघवजी : सभापति जी, यह बात बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कितने समय से लोग प्रतीक्षा सूची मे हैं .....(**व्यवधान**)..... तीन-तीन साल से लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और उन को टेलीफोन नहीं मिला हैं .....(**व्यवधान**).....

श्री सुख राम : अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आप की आपत्ति का उत्त दूंगा। सभापति जी, जैसेकि माननीय सदस्यों ने कहा कि एक-एक साल तक उन के केसेज नहीं हुए यह बड़े अफसोस की बात हैं। अगर आप लिखकर दे कि किस-किस का है तो मैं उस के मुताबिक एक्शन लूंगा, जहां यह देरी हुई हैं। मगर हमारे निर्देश हैं कि मेंबर आफ पार्लियामेंट के जो आउट आफ टर्न अलाटमेंट्स हैं वह 30 डेज के अंदर होना चाहिए।

मौलान ओबैदुल्ला खान आजमी : नहीं हो रहा हैं .....(**व्यवधान**).....

†**مولانا عبیداللہ خاں اعظمی**: نہیں ہو رہا ہے..."مداخلت"...

श्री सतीश अग्रवाल : कोई भी मेंबर खड़ा होकर कह दें कि 30 डेज में इंस्टाल हुआ हो? एक का भी नहीं हुआ हैं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : पैसा मांगते हैं .....(**व्यवधान**).....

†**مولانا عبیداللہ خاں اعظمی**: پیسہ مانگتے ہیں..."مداخلت"...

श्री मोहम्मद सलीम : अपार्ट फ्राम डिले, अगर नागपुर के लिए रिकमेंडेशन होता हैं तो वह मध्य प्रदेश के लिए भेज देते हैं।

†**شری محمد سلیم**: اپارٹ فروم ڈے۔ اگر ناگپور کیلئے ریکمینڈیشن ہوتا ہے۔ تو وہ مدھیہ پردیش کیلئے بھیجدیتے ہیں۔

श्री सतीश अग्रवाल : आप एक कमेटी बना दीजिए इस की जांच के लिए।

श्री सुख राम : मैंने यह कहा हैं कि इस की बाकायदा मंथली और 3 महीने में हम रिव्यू करते हैं। उस में कुछ केसेस में ऐसा पाया गया हैं कि जिन्होने अपने केसेस रिकमेंड किए उन्होने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या कहीं-कहीं एड्रेसेस में कमी थी।

Please listen to what 1 am going to say.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: It is provided in the rules that those cases which have been recommended by the MPs should be decided within thirty days. We send the photo copies of the registration,

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : सर, रजिस्ट्रेशन की कापी लगाकर भेजी जाती हैं और ऐसा भी होता हैं कि अगर दो – एक आदमी का भी हो गया है तो बगैर पैसा लिए नहीं करते। बगैर पैसा दिए टेलीफोन नहीं लगाते । खुलमखुल्ला पैसा चल रहा हैं आप के विभाग में .....(**व्यवधान**).....

श्री सुख राम: मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अभी मैं सारी सूची देखकर जहां-जहां डिले हुई हैं, अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी की वजह से डिले हुऐ हैं उन के ऊपर एक्शन भी लूंगा और यह एंश्योर करूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो आउट ऑफ कर्न कोटा हैं, वह जल्दी होना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : यह हम आज पहली बार नहीं उठा रह हैं .....(**व्यवधान**).....

MR. CHAIRMAN : Q.No. 24. Shri Virendra Kataria. (*Interruptions)* The Minister said that he will look into it. (*Interruptions)* I have gone to the next question. You have taken a lot of time for this question. *{Interruptions)*

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, the action taken should be reported to the House.

US views about Pak Terrorism

*44. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned "Wisner not for Pak as terrorist State" which appeared in the 'Hindustan Times', dated the 21st August, 1995;

(b) if so, what is the reaction of Government thereon;

(c) whether the recent release of the U.S. State Department's own Annual Report on Pattern of Global Terrorism indicates Pak's involvement in terrorist activities; and

(d) the steps being taken by Government to reconcile with these two contradicitory statements of the U.S. Government?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes sir.

(b) The news item refers to the reluctance of the US to declare Pakistan a terrorist State for want of proof and specific findings. Government do not share the view of the US, which the US Ambassador has reitereated in the press conference, that there was no proof of Pakistan Govenrment's ' involvement in terrorist activities in India. On the contrary, the available evidence, both within India and within the US system, clearly establishes that Pakistan is actively engaged in financing, abetting, training and arming of militants and infiltration into India, particularly J&K.

†[]Transliteration in Arabic Script